डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 से 28 फरवरी, 2022, डिस्पेच दिनांक 16 फरवरी, 2022

| वर्ष 65 | अंक 18 | भोपाल | 16 फरवरी, 2022 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

माँ, बहन, बेटियों के सशक्तीकरण के लिए काम करना मेरे जीवन का मिशन - मुख्यमंत्री श्री चौहान

महिलाएँ रूपए-पैसे के डिजिटल लेन-देन को अपनाएँ

नशामुक्ति, बाल विवाह रोकने, स्वच्छता, पोषण और पर्यावरण-संरक्षण के लिए भी कार्य करें महिला स्व-सहायता समूह

राज्य सरकार शीघ्र क्रियान्वित करेगी लाड़ली लक्ष्मी योजना-दो

जन्म से जीवन पर्यंत है महिला सशक्तीकरण की व्यवस्था

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्व-सहायता समूह के सदस्यों को वर्चुअली वितरित किए 300 करोड़ रूपए के ऋण

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यदि काम करने की तड़प हो तो बहनें चमत्कार कर सकती हैं। माता, बहन, बेटियाँ अभाव और गरीबी में रहने तथा ताने सुनने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वह अभी तक नहीं मिला है। बेटा-बेटियों में भेद किया जाता है। माँ, बहन, बेटी के सशक्तीकरण के लिए काम करना मेरे जीवन का मिशन है, यह मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने जो योजनाएँ बनाई उनका उद्देश्य ग्राम स्तर तक महिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित करना रहा। मुख्यमंत्री श्री चौहान कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में ग्रामीण राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्व-सहायता समूह के सदस्यों को बैंक ऋण वितरित करने कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्व-सहायता समूह के सदस्यों को 300 करोड़ रुपए के बैंक ऋण सिंगल क्लिक से वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत स्तर पर समूह के सदस्यों से वर्चुअल संवाद भी किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सारगर्भित प्रशिक्षण सामग्री से परिपूर्ण आजीविका कैलेंडर का विमोचन भी किया। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल तथा प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री उमाकांत उमराव उपस्थित थे। दीप जलाने और मध्यप्रदेश गान के साथ आरंभ हुए कार्यक्रम में देवास जिले में बने पोषण आहार संयंत्र पर केंद्रित फिल्म का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम से सभी जिले और पंचायतें वर्चुअली जुड़ीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आरंभ करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि महिलाओं के जन्म से लेकर जीवन पर्यंत उनके सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से व्यवस्था की गई है। प्रदेश में संबल योजना भी क्रियान्वित है।

गर्भवती माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, बेटी के जन्म होने पर लाड़ली लक्ष्मी योजना, बेटी स्कूल जाए तो नि:शुल्क पुस्तकें और स्कूल यूनिफार्म, बेटी दूसरे गाँव में पढ़ने जाए तो नि:शुल्क सायकिल, बेटी बारहवीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो तो गाँव की बेटी योजना का लाभ, बेटी कॉलेज जाए तो प्रतिभा किरण योजना के लाभ की व्यवस्था है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

श्री संजय गुप्ता सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक बने

भोपाल। राज्य शासन द्वारा श्री नरेश पाल कुमार, आईएएस के सेवानिवृत्ति होने पर श्री संजय गुप्ता को आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें म.प्र. के पद पर पदस्थ किया गया है। श्री संजय गुप्ता द्वारा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें म.प्र. का पदभार ग्रहण कर लिया गया।

सहकारी संस्थाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य अन्य संस्थाओं के लिए प्रेरणा बनेंगे

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहकारी संस्थाओं को पुरस्कृत किया

भोपाल : सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि सहकारी संस्थाओं द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य अन्य संस्थाओं के लिये कार्य करने की प्रेरणा बनेंगे। मंत्री डॉ. भदौरिया ने आज मंत्रालय में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और सहकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहकारी समितियों को क्षेत्रीय उत्कृष्टता एवं मेरिट पुरस्कार-2021 प्रदान किये। अपर मुख्य सचिव श्री अजीत केसरी ने पुरस्कृत संस्थाओं के कार्यों को सफलता की कहानी के तौर पर प्रचारित करने के लिये कहा, ताकि दूसरी संस्थाएँ भी इनका अनुकरण कर सकें।

विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिये इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहकारी संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) का प्रथम पुरस्कार आदिम-जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित गोगावां, जिला खरगोन और द्वितीय पुरस्कार सेवा सहकारी समिति मर्यादित जामसावली, जिला छिन्दवाड़ा को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक समिति (क्रेडिट) में प्रथम पुरस्कार सद्गुरु साख सहकारी संस्था मर्यादित, जिला धार को और द्वितीय पुरस्कार श्री गुजराती रामी माली समाज नवयुवक साख सहकारी संस्था मर्यादित

(शेष पृष्ठ 6 पर)

उद्यानिकी कृषकों के सुझाव पर बनेगी विभाग की कार्य-योजना

संभाग स्तर पर करेंगे कृषकों से चर्चा ● विभागीय समीक्षा बैठक में राज्य मंत्री श्री कुशवाह

भोपाल : उद्यानिकी विभाग की वर्ष 2022-23 की कार्य-योजना उद्यानिकी कृषकों के सुझाव पर बनाई जाएगी। उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह ने मंत्रालय में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में यह बात कही। अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री जे.एन. कंसोटिया, उद्यानिकी आयुक्त श्री ई. रमेश कुमार और एम.डी.एम.पी. एग्रो श्री राजीव कुमार जैन उपस्थित थे।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि वे स्वयं उद्यानिकी कृषकों से संभागवार बैठक कर सुझाव लेंगे। संभागीय बैठकों में प्रत्येक जिले से 20 से 40 कृषकों को आमंत्रित किया जाएगा। कृषकों से चर्चा कर उद्यानिकी विभाग में प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों पर सुझाव लिए जाएंगे। प्राप्त सुझावों के आधार पर आगामी वर्ष की विभागीय कार्य-योजना बनाई जाएगी।

प्रत्येक जिले में होगा माली प्रशिक्षण केन्द्र

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि जिला स्तर पर माली प्रशिक्षण केन्द्र बनाये जायेंगे। प्रत्येक जिले में एक नर्सरी को माली प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मांग के अनुसार इच्छुक युवाओं और व्यक्तियों को माली कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो 3 माह की अवधि का होगा।

नर्सरियों को अतिक्रमण मुक्त रखें

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि कुछ जिलों की नर्सरी क्षेत्र में अतिक्रमण होने की जानकारी उनके ध्यान में आई है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभाग की नर्सरियों को अतिक्रमण मुक्त रखें। जिन नर्सरी क्षेत्र पर अतिक्रमण है, उसे एक सप्ताह में हटवाना सुनिश्चित करें।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने प्रदेश के संतरा, प्याज, लहसुन आदि अन्य उद्यानिकी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस पहल करने के निर्देश दिए। बैठक में विभाग की अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

अपेक्स बैंक के प्रशासक का कार्यभार श्री संजय गुप्ता (आई.ए.एस.)

भोपाल । आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश ने बैंक के टी0टी0नगर स्थित मुख्यालय भवन में पहुँचकर ग्रहण किया । कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सभी कक्षों के वरिष्ठ अधिकारीगण के साथ बैठक ली । श्री गुप्ता ने विशेष रूप से कृषि ऋण वितरण एवं उपार्जन के कार्य पर विस्तृत चर्चा की ।

इस अवसर पर बैंक के प्रबंध संचालक श्री पी.एस.तिवारी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्रीमती अरुणा दुबे, श्री के.के. द्विवेदी, सहायक महाप्रबंधक श्री आर.एस.चंदेल, श्री के.टी. सज्जन, श्री अरविंद बौद्ध, वि.क.अ, प्रबंधक श्रीमती ज्योति उपाध्याय, श्री विनोद श्रीवास्तव, उप-प्रबंधक श्री समीर सक्सेना, श्री करुण यादव, श्री आर.व्ही.एम. पिल्लई, श्री अरविंद वर्मा, श्री अजय देवड़ा, एस.के.जैन, सहायक प्रबंधक, शाखा प्रबंधक टी0टी0नगर श्री कमल मकाश्रे, केडर अधिकारी श्री पी.एस.

धनवाल, श्री के.के.रायकवार, जनसम्पर्क अधिकारी अभय प्रधान, अपेक्स बैंक कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष श्री अभिषेक अग्रवाल एवं पदाधिकारियों ने प्रशासक श्री संजय गुप्ता का पुष्प गुच्छों से स्वागत किया।

बैतूल जिले के जैविक गेहूँ, चावल की माँग बढ़ रही है अन्य राज्यों में

भोपाल : बैतूल जिले के गाँव सोहागपुर के किसान स्वदेश चौधरी, जैविक खेती अपनाने वाले जिले के किसानों में प्रमुख हैं। वे अपनी 25 एकड़ जमीन में से 5 एकड़ में गेहूँ, चावल, धनिया, तूअर, मटर, चना, मेथी और लहसुन की जैविक खेती कर रहे हैं। स्थानीय बाजार के साथ उनका जैविक गेहूँ और चावल छत्तीसगढ़ के रायपुर, महाराष्ट्र के नागपुर, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थाई ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है। जैविक उत्पादों की गुणवत्ता के कारण स्वदेश चौधरी के जैविक उत्पादों की माँग निरंतर बढ़ती जा रही है। श्री चौधरी बताते हैं कि वे पिछले 12 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। उनके जैविक उत्पाद मध्यप्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था भोपाल से पंजीकृत हैं। पाँच एकड़ जमीन में से वे साढ़े चार एकड़ में गेहूँ, चावल और मूंगफली की फसल और शेष आधे एकड़ में जैविक धनिया, तूअर, मटर, चना, मेथी और लहसुन उगाते हैं। उन्हें रबी सीजन में लगभग 50 क्विंटल गेहूँ और खरीफ सीजन में इतना ही चावल मिल जाता हैं। मानव स्वास्थ्य के अनुकूल जैविक उत्पादों की माँग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसमें लाभ भी अच्छा मिल जाता है। इसलिए स्वदेश चौधरी जैविक खेती और जैविक खेती का क्षेत्र बढ़ाने का विचार कर रहे हैं।

स्वदेश चौधरी बैतूल जिला मुख्यालय पर स्थापित जैविक हाट बाजार के माध्यम से भी गेहूँ, चावल और अपने अन्य जैविक उत्पाद बेचते हैं। श्री चौधरी ने बताया कि इन सभी जैविक उत्पादों से उन्हें 7 लाख रूपये की वार्षिक आय होती है।

इस बार छन्ना लगाकर होगी गेंहू की खरीद

नई व्यवस्था – 25 मार्च से 3500 से ज्यादा केन्द्रों पर समर्थन मूल्य से की जाएगी खरीद

भोपाल। प्रदेश में इस बार समर्थन मूल्य पर गेंहू छन्ना लगाकर खरीद जाएगा। जय किसान उपज लेकर उपार्जन केंन्द्र पर आएगा तो उसे छन्ने से छानकर लिया जाएगा, ताकि गुणत्तायुक्त अनाज की ही खरीद हो। इससे न तो समितियों को कोई परेशानी होगी और न ही किसानों को भुगतान में समस्या आएगी। उपज किसान की ही हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी पहचान अंगूठे का निशान लेकर की जाएगी। आधार के बायोमीट्रिक सत्यापन के बाद ही उपज बेची जा सकेगी। किसान का पंजीयन भी तभी होगा, जब उसका भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड से हो। इसमें अंतर होने पर तहसील कार्यालय से सत्यापन कराया जाएगा और सही होने पर ही पंजीयन मान्य होगा। समर्थन मूल्य (एक हजार 975 रूपये प्रति क्विंटल) पर उपार्जन 25 मार्च से साढ़े तीन हजार से ज्यादा केन्द्रों पर प्रारंभ होगा। सरकार का अनुमान है कि इस बार 140 लाख टन तक गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद हो सकती है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद में गड़बड़ियों को रोकने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन किया है। किसानों को पंजीयन कराने में असुविधा न हो, इसके लिए अब एम.पी. आनलाइन कियोस्क, कामन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र और साइबर कैफे पर जाकर भी पंजीयन करा सकते है। इसके लिए उन्हें पचास रूपये शुल्क देना होगा।

प्रत्येक शासकीय उचित मूल्य दुकान, प्रत्येक कार्य दिवस पर निर्धारित समयावधि मे खोली जाए - कलेक्टर

उमरिया : कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के प्रावधानों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकाने प्रति कार्य दिवस निर्धारित समय पर खोलने एवं बंद किये जाने का प्रावधान है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत हितग्राहियों को सुगमतापूर्वक वितरण सुनिश्चित करने, व्यवस्था को सुदृढ एवं पारदर्शी बनाने के साथ वास्तविक हितग्राहियों को उनके लाभ की समय पर प्रदायगी सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से जिले में संचालित प्रत्येक शासकीय उचित मूल्य दुकान, प्रत्येक कार्य दिवस पर निर्धारित समयावधि में खुली रहे, यदि दुकाने प्रत्येक कार्य दिवस/समयावधि पर नहीं खुलती है तो विक्रेता को जितने दिवस दुकान खोलकर खाद्यान्न वितरण का कार्य करेंगे उतने दिवस का ही वेतन भुगतान किया जाए। लैम्प्स प्रबंधक, एईपीडीएस पोर्टल से प्रत्येक माह चेक कर दुकान जितने दिवस एक्टिव रही उसी के अनुसार विक्रेताओं को वेतन भुगतान करेंगे, और कटौती की गई राशि विभागीय मद में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की एक प्रति जिला खादय कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चार आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रतीक स्वरूप मंत्रालय में दिए स्मार्ट फोन

प्रदेश में कुपोषण समाप्ति में सहायक होंगे मोबाइल फोन

श्रेष्ठ कार्य के लिये आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, गोद लेने वाले व्यक्ति, सुपरवाइजर और अधिकारी होंगे पुरस्कृत

सीहोर जिले में वितरित होंगे 1465 स्मार्ट फोन, प्रदेश में एक लाख का लक्ष्य

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कुपोषण के कलंक को दूर करने के लिए हम अब अधिक कामयाब होंगे, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की वैज्ञानिक ढंग से जाँच हो सकेगी। पहले जहाँ 11 तरह के रजिस्टर में स्वास्थ्य और पोषण की जानकारियाँ दर्ज करनी होती थी वहीं अब एक स्मार्ट फोन के माध्यम से यह कार्य आसान हो जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में इस व्यवस्था को लागू किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मंत्रालय में सीहोर जिले की चार आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सुश्री रेखा बरेला, मनीषा प्रजापति, दीपा गोहिया और रेखा कराते को प्रतीक स्वरूप स्मार्ट फोन प्रदान किए। सीहोर जिले की 1465 आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्रेष्ठ कार्य के लिये जिला और राज्य स्तर की आँगनवाड़ी, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, गोद लेने वाले व्यक्ति, सुपरवाइजर और महिला बाल विकास अधिकारी पुरस्कृत होंगे।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, विधायक श्री सुदेशराय, श्री करण सिंह वर्मा, श्री सीताराम यादव, सीहोर टाउन हाल से कार्यक्रम में वर्चुअली सम्मिलित हुए। प्रदेश में करीब एक लाख स्मार्ट फोन वितरण का लक्ष्य है। प्रथम चरण में प्रदेश के 16 जिलों की 27 हजार 817 आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन एवं 972 पर्यवेक्षक को टेबलेट वितरित किये गए। अब 36 जिलों की 69 हजार 316 आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा 2,429 पर्यवेक्षकों को स्मार्ट फोन क्रय कर जिला स्तर से वितरित किए जा रहे हैं।

कुपोषण के खात्मे के लिए चाहिए सभी का सहयोग

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्मार्ट फोन कुपोषण समाप्ति का माध्यम बनेगा। बच्चों में कम वजन होना, एनिमिया की समस्या और कद छोटा होना ऐसी विकृतियाँ हैं, जो पर्याप्त भोजन के अभाव में होती हैं। प्रदेश में कुपोषण समाप्ति के अनेक प्रयास हुए हैं, जिसके फलस्वरूप कुपोषण को कम करने में सफलता भी मिली है। लेकिन जब तक सभी बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे, हम चैन की साँस नहीं लेंगे। कुपोषण के खात्मे के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। हम दिन रात परिश्रम करके अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे।

मुख्यमंत्री ने गोद ली मथार की आँगनवाड़ी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि वे सीहोर जिले के आँगनवाड़ी केंद्र, मथार को गोद ले रहे हैं। उन्होंने आँगनवाड़ियाँ गोद लेने के लिए जन-प्रतिनिधियों से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से बच्चों को सपोषित करने के कार्य में आसानी होगी। जिन व्यक्तियों ने आँगनवाड़ी गोद ली हैं, वे माह में एक बार वहाँ का भ्रमण जरूर करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एक पोषण मटका रखने और उसमें मूँग, दाल, चना और अन्य खाद्यान्न की व्यवस्था का भी आग्रह किया।

पोषण ट्रेकर एप की नई व्यवस्था

महिला एवं बाल विकास विभाग प्रदेश में पोषण अभियान का संचालन 453 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में स्वीकृत 97 हजार 135 आँगनवाड़ी और मिनी आँगनवाड़ी केंद्रों से कर रहा है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित वास्तविक समयबद्ध निगरानी मोबाइल आधारित पोषण ट्रेकर एप (एप्लीकेशन) की व्यवस्था की गई है। स्मार्ट फोन से पोषण ट्रेकर एप का उपयोग कर आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आँगनवाड़ी केंद्रों में दी जाने वाली सेवाओं की दैनिक जानकारी की प्रविष्टी की जाती है। जानकारी का अनुश्रवण ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतिदिन किया जाता है। आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्मार्ट फोन पर पोषण ट्रेकर का उपयोग करने से जहाँ प्रतिदिन रजिस्टरों के संधारण का काम कम होगा, वही एप्लीकेशन से आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रतिदिन दैनिक कार्यों के संबंध में तैयार सूचना प्राप्त होगी, जिसमें उन्हें गृह भेंट में टीकाकरण तथा अन्य सेवाओं के लिए किन हितग्राहियों को चुनना है। आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के दायित्व में हितग्राहियों के घरों में जाकर परामर्श देना और सूचनाएँ देना भी शामिल है। नई व्यवस्था से यह कार्य भी आसान हो जाएगा। पोषण ट्रेकर से आँगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने केंद्र में दर्ज समस्त हितग्राहियों की सूची अपने मोबाइल पर कहीं भी किसी भी समय पर देख सकती हैं, जिससे हितग्राहियों की निगरानी करना आसान होगा। आँगनवाड़ी केंद्र में दर्ज 5 साल आयु तक के बच्चों की वृद्धि की निगरानी भी आसान हो जाएगी। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बच्चों का वजन एवं ऊँचाई दर्ज करने पर तत्काल बच्चे के कुपोषण का स्तर परिलक्षित होने लगेगा। अब आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को ग्रोथ रजिस्टर नहीं भरना पड़ेगा। पोषण ट्रेक्टर से गर्भवती महिला का पंजीयन करने पर आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रतिदिन किस गर्भवती महिला की जाँच करानी है अथवा किस गर्भवती महिला को गृह भेंट के माध्यम से परामर्श देना है, यह जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। पोषण ट्रेकर एप्लीकेशन के संचालन के लिए नेट कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश की समस्त आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 200 रूपये प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है। एप्लीकेशन में निर्धारित मापदंडों अनुसार जानकारी भरने पर आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रूपये की राशि तथा आँगनवाड़ी सहायिका को 250 रूपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।

प्रदेश में प्रथम चरण में 27 हजार और द्वितीय चरण में 69 हजार स्मार्ट फोन वितरित करने का कार्य विभाग की प्राथमिकता में है। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साथ ही आँगनवाड़ियों को गोद लेने का कार्य भी निरंतर चल रहा है। प्रदेश में अब तक 71 हजार आँगवाड़ियों को जन-प्रतिनिधि और नागरिकों ने गोद लिया गया है।

समर्थन मूल्य पर गेंहू का विक्रय करने हेतु कृषकों को कराना होगा पंजीयन

किसानों की सुविधा के लिये ऑनलाइन होगा पंजीयन

हरदा : राज्य शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार ऐसे किसान जो अपना गेंहू समर्थन मूल्य पर विक्रय करना चाहते हैं, उन्हें पंजीयन कराना होगा। किसानों की सुविधा के लिये ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की गई है। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये किसानों के पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो गया है। जिले में निर्धारित पंजीयन केन्द्रों के अतिरिक्त एम.पी. ऑनलाइन, कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र, एम.पी. किसान एप से भी किसान पंजीयन करा सकते हैं। सिकमीदार एवं वनाधिकार पट्टाधारी किसानों के पंजीयन समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्र पर ही होंगे। 'नवीन पंजीयन, उपार्जन एवं भुगतान व्यवस्था में संशोधन' नवीन पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखे। नवीन व्यवस्था अनुसार पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड प्रविष्ट कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब किसानों को उपार्जित फसल का भुगतान उनके आधार नंबर से लिंक खाते में सीधे प्राप्त होगा। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। फसल बेचने के लिये एसएमएस प्राप्ति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। किसान फसल बेचने के लिए निर्धारित पोर्टल से नजदीक के उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाईम स्लॉट का स्वयं चयन 7 मार्च 2022 से 20 मार्च 2022 तक कर सकेंगे। जिले के सभी किसनों से अपील की गई है कि यदि वह समर्थन मूल्य पर गेहूं का विक्रय करना चाहते है तो वह उपरोक्त व्यवस्था अनुसार पंजीयन केन्द्रों तथा एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र, एम.पी. किसान एप के द्वारा 05 मार्च 2022 तक पंजीयन करा सकते हैं।

प्रदेश में गरीब, बेसहारा और बेघरबारों को भी मिली नि:शुल्क खाद्यान्न पर्ची - खाद्य मंत्री श्री सिंह

धार की कड़वी बाई को मिली प्रदेश की प्रथम पात्रता पर्ची

भोपाल : शासन द्वारा नि:शुल्क राशन वितरण योजना के तहत वितरित की गई खाद्यान्न पर्ची के दायरे को और अधिक लचीला किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान की मंशा के अनुसार शासन द्वारा प्रदेश के गरीब, बेघर, बेसहारा ऐसे लोग, जिनकी आय का कोई स्रोत नहीं है, को भी नि:शुल्क खाद्यान्न पर्ची वितरण के लिये स्वीकृति दी गई है। गुरुवार को धार जिले की कड़वी बाई पत्नी श्री कन्हैया लाल को नि:शुल्क खाद्यान्न पर्ची जारी की गई।

खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि सतना को छोड़कर प्रदेश के शेष जिलों में सर्वे कराया गया था। सर्वे में 10 हजार 840 लोग इस श्रेणी के पाये गये हैं। इसके लिये 4098 स्थानों पर कैम्प लगाये गये। लगभग 4 हजार सर्वेक्षण दल गठित किये गये। इसमें 5143 परिवारों का सर्वे कराया गया था। सर्वे में जबलपुर में सर्वाधिक 518 परिवारों के 2677 सदस्यों को पर्ची वितरित की जायेंगी।

शासन द्वारा नि:शुल्क राशन वितरण योजना के तहत वितरित की गई खाद्यान्न पर्ची के दायरे को और अधिक लचीला किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान की मंशा के अनुसार शासन द्वारा प्रदेश के गरीब, बेघर, बेसहारा ऐसे लोग, जिनकी आय का कोई स्रोत नहीं है, को भी नि:शुल्क खाद्यान्न पर्ची वितरण के लिये स्वीकृति दी गई है। गुरुवार को धार जिले की कड़वी बाई पत्नी श्री कन्हैया लाल को नि:शुल्क खाद्यान्न पर्ची जारी की गई।

डेढ़ दशक में उद्यानिकी फसलों के रकबे और उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि

भोपाल :मध्यप्रदेश में पिछले डेढ़ दशक में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल में 5 गुना और उत्पादन में 7 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2006 में उद्यानिकी फसलों का कुल रकबा 4 लाख 69 हजार हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 23 लाख 43 हजार हेक्टेयर हो गया। उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि होने का सीधा प्रभाव उत्पादन में हुई वृद्धि में भी दिखाई देता है। इस अवधि में उद्यानिकी फसलों का उत्पादन भी 42 लाख 98 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर अब सात गुना से अधिक 340 लाख 31 हजार मीट्रिक टन हो गया है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सुविचारित नीतियों और दूरदर्शिता से उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन में हुई इस उल्लेखनीय वृद्धि का ही परिणाम है कि मध्यप्रदेश मसाला, सब्जी, फल और फूल उत्पादन में देश के पहले 5 राज्यों में शामिल है। प्रदेश मसाला फसलों के उत्पादन में देश में पहले, सब्जी में तीसरे, फूल में चौथे और फल उत्पादन में पाँचवें स्थान पर है।

प्रदेश में वर्ष 2006 का फलों की खेती का रकबा 46 हजार 777 हेक्टेयर से बढ़कर 4 लाख 5 हजार हेक्टेयर और उत्पादन 11 लाख 73 हजार मीट्रिक टन से 82 लाख 44 हजार मीट्रिक टन बढ़ा है। इस अवधि में सब्जी का क्षेत्र एक लाख 96 हजार हेक्टेयर और उत्पादन 27 लाख 97 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर क्षेत्र 10 लाख 40 हजार हेक्टेयर और उत्पादन 206 लाख 31 हजार मीट्रिक टन हो गया। मसाला फसलों का क्षेत्र भी 2 लाख 7 हजार 563 हेक्टेयर और उत्पादन 2 लाख 33 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 82 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 46 लाख 37 हजार मीट्रिक टन हो गया। फूलों की खेती जो वर्ष 2006 में मात्र 3 हजार 667 हेक्टेयर में होती थी, वह 35 हजार 554 हेक्टेयर में हो रही है।

औषीधीय और सुगंधित फूलों की खेती

प्रदेश में औषधीय एवं सुगंधित फूलों की खेती जो मात्र 15 हजार 650 हेक्टेयर में होती थी, अब 42 हजार 956 हेक्टेयर में हो रही है।

उद्यानिकी फसलों की खेती में प्रदेश देश के पहले पाँच राज्यों में

वर्ष 2018 के उद्यानिकी की राष्ट्रीय सांख्यिकी में मध्यप्रदेश ने देश के कुल 8123.87 हजार मीट्रिक टन मसाला उत्पादन में 1191.81 हजार मीट्रिक टन का योगदान किया है। यह देश के सकल मसाला उत्पादन का 14.67 प्रतिशत है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में देश के कुल 184394.51 हजार मीट्रिक टन उत्पादन में मध्यप्रदेश ने 17545.48 हजार मीट्रिक टन सब्जी का योगदान कर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाद तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस तरह देश के सब्जी उत्पादन में मध्यप्रदेश का योगदान 9.52 प्रतिशत रहा।

फल और फूलों के उत्पादन में भी विशिष्ट स्थान

प्रदेश फूलों के उत्पादन में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बाद देश में चौथे स्थान पर है। देश के फूल उत्पादन में प्रदेश का हिस्सा 10.15 प्रतिशत है। देश के कुल 97357.51 हजार मीट्रिक टन फल उत्पादन में 7416.91 हजार मीट्रिक टन योगदान कर मध्यप्रदेश आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात के बाद पाँचवें स्थान पर है। इस तरह फलों के उत्पादन में प्रदेश का देश के उत्पादन में 7.62 प्रतिशत हिस्सा है।

उद्यानिकी फसलों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि

पिछले डेढ़ दशक में प्रदेश में उद्यानिकी फसल उत्पादों के भण्डारण के लिये बढ़ी संख्या में कोल्ड-स्टोरेज और भण्डार-गृह बनाये गये हैं। वर्ष 2008 में प्रदेश में करीब एक लाख 19 हजार मीट्रिक टन क्षमता के 2,890 प्याज भण्डार-गृह थे, जो अब 3 लाख 79 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा क्षमता के 8,530 भण्डार गृह हो गये हैं।

एक जिला-एक उत्पाद

जिलों के स्थानीय परिवेश और उद्यानिकी कृषकों द्वारा की जा रही फसलों की खेती को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिये एक उत्पाद का चयन किया गया है। आगर-मालवा और राजगढ़ के लिये संतरा/नींबू, अलीराजपुर, धार और सिवनी के लिये सीताफल, अनूपपुर, बैतूल, उमरिया, सीधी और सिंगरौली के लिये आम, अशोकनगर, दमोह, दतिया, झाबुआ, कटनी, रायसेन, सागर, सतना और शिवपुरी के लिये टमाटर, बालाघाट, डिण्डोरी और मण्डला के लिये कोदो-कुटकी, बड़वानी, निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले के लिये अदरक, भिण्ड के लिये बाजरा, भोपाल, होशंगाबाद, सीहोर और श्योपुर के लिये अमरूद, बुरहानपुर के लिये केला, छतरपुर के लिये पान, छिन्दवाड़ा, देवास, ग्वालियर और इंदौर के लिये आलू, गुना और नीमच के लिये धनिया, हरदा, शाजापुर, खण्डवा, उज्जैन और विदिशा के लिये प्याज, जबलपुर के लिये मटर, खरगोन के लिये मिर्च, मंदसौर और रतलाम के लिये लहसुन, मुरैना के लिये सरसों, नरसिंहपुर के लिये गन्ना, शहडोल और रीवा के लिये हल्दी और पन्ना के लिये आँवला का एक जिला-एक उत्पाद के रूप में चयन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा चयनित उत्पाद की खेती, भण्डारण, प्र-संस्करण और विपणन के क्षेत्र में कार्य करने में उद्यानिकी कृषकों को मदद दी जा रही है।

गाँव की सूरत बदलने का करना है काम : मुख्यमंत्री श्री चौहान

- हर घर पहुँचेगा नल से जल
- कच्चे मकानों की जगह बनाये जायेंगे पक्के मकान
- पानी की एक-एक बूँद को सहेजें
- स्कूल और आँगनवाड़ियों में भी पहुँचाया जा रहा है नल से जल
- युवाओं के लिये सरकार चला रही है स्व-रोजगार अभियान
- पक्के मकान के साथ स्वच्छता, बिजली, राशन, शिक्षा और उपचार सरकार की प्राथमिकता
- आवास प्लस योजना का सर्वे कर नये हितग्राही जोड़ेंगे
- मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन से लाभान्वित 4 हजार ग्रामों के निवासियों को किया संबोधित
- मिशन की जल एवं स्वच्छता समिति सदस्यों से किया संवाद
- ग्रामीणों ने पेयजल की सहज उपलब्धता के लिये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लिखे धन्यवाद-पत्र
- मुख्यमंत्री के साथ ग्रामीण महिलाओं ने साझा किये अपने सुखद अनुभव

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकार गाँव की सूरत बदलने का काम कर रही हैं। गाँव में पेयजल की सहज उपलब्धता के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन मिशन की सौगात दी है, जो विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के लिये वरदान साबित हो रही है। मिशन से प्रदेश के सभी ग्रामीण अंचलों में एकल और समूह पेयजल योजना बनाकर युद्ध-स्तर पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिशन से अब तक 4 हजार से अधिक ग्रामों के सौ फीसदी घरों में नल से जल की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इन्हें मिलाकर अब तक मिशन से प्रदेश के 46 लाख से अधिक परिवारों को नल से जल उपलब्ध हो गया है। साथ ही जल की शुद्धता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज जल जीवन मिशन से प्रदेश के लाभान्वित ग्रामों के रहवासियों से वर्चुअल संवाद कर रहे थे। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल भोपाल में हुए इस संवाद में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मलय श्रीवास्तव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सांसद, विधायक, जन-प्रतिनिधि, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य और मिशन से लाभान्वित ग्रामीण महिलाएँ वर्चुअली शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुधारने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। आवासहीन परिवारों को आवास सुविधा और अब गाँव-गाँव, घर-घर पेयजल की व्यवस्था जल जीवन मिशन से की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता में गाँव में बिजली, पानी, शिक्षा, राशन, उपचार, स्व-रोजगार के साथ स्वच्छता भी है। सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली इन सुविधाओं को हम जन-भागीदारी से संचालित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामीणों से पानी और बिजली के अपव्यय को रोकने की अपील भी की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं से संवाद में यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि वे घर में नल से आ रहे जल का महत्व भली-भाँति जानती हैं। जल के महत्व को उनसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मिशन के पूर्व वे 2-2 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर पानी लाया करती थी। अब उनकी समस्या का निदान हो गया है। अपने घर में नल से जल आता देख सुखद आनंद की अनुभूति होती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्ष 2024 तक प्रदेश के सभी ग्रामों में नल से जल पहुँचाया जायेगा। शुद्ध पेयजल की उपलब्धता से लोगों को अनेक रोगों से भी मुक्ति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन से हर गाँव पेयजल की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये 45 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसमें 50 प्रतिशत केन्द्रांश और 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय की जा रही है। अभी तक जिन 4 हजार से अधिक ग्रामों में मिशन की परियोजना लागू हुई है, उसके संचालन एवं संधारण का काम ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संवाद के दौरान सभी समिति सदस्यों को धन्यवाद दिया और उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की।

मुख्यमंत्री का संवाद

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल जिले के फंदा विकासखण्ड के बिलखिरिया ग्राम पंचायत की सुश्री अनीता मालवीय से गाँव में पहले की पेयजल व्यवस्था और मिशन में घर-घर लगे नल के संबंध में जानकारी ली। सुश्री मालवीय ने बताया कि पहले एक-दो किलोमीटर से पानी लाना पड़ता था। हमारे घर में जल से नल मिलेगा, ऐसा हमने सोचा भी नहीं था।

मुख्यमंत्री श्री चौहान से जल जीवन मिशन में लाभांवित सीहोर जिले के ग्राम सतपिपलिया के श्री मंगलेश, अनूपपुर जिले के ग्राम हर्राखेड़ा की श्रीमती ममता, अशोकनगर जिले के ग्राम सेहराई की श्रीमती रचना विश्वकर्मा, जबलपुर जिले के ग्राम नीमखेड़ा के श्री विपिन गर्ग, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम मऊ की सुश्री वैशाली डोगले, दमोह जिले के ग्राम सिमरी शुक्ला की श्रीमती किरण शुक्ला, देवास जिले के ग्राम बरखेड़ा कायम के श्री ज्ञानेश्वर, मण्डला जिले के ग्राम भंवरदा की सुश्री भगवती, सिवनी जिले के ग्राम भुनगापार के श्री शरीफ खान, रीवा जिले के ग्राम जुड़भनियां मुरली की सुश्री सविता, नीमच जिले के ग्राम उम्मेदपुरा के श्री दुर्गाशंकर और पन्ना जिले के ग्राम रामनगर के श्री राकेश सोनी ने अपने सुखद अनुभव साझा किये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मिशन में लाभान्वित ग्रामों की ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, ग्रामीण और जन-प्रतिनिधियों से भी वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि बहनों के चेहरे की मुस्कुराहट मेरे मुख्यमंत्री बनने की सार्थकता है। हमारे गाँव की बहन-बेटियों का आधा जीवन तो जल की व्यवस्था में ही बीत जाता था। अब घर में नल कनेक्शन से मिल रहे पानी से उन्हें काफी राहत महसूस हो रही है और पानी की जद्दोजहद में निकलने वाला समय उनके और परिवार की आर्थिक उन्नति में काम आयेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामीणों से आग्रह किया कि 45 हजार करोड़ से हो रहे कार्यों की देख-रेख अपने कार्य समझकर करें। इससे जल-प्रदाय योजनाओं का संचालन-संधारण बेहतर होगा और उसका लाभ भी लम्बे समय तक मिलता रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान को सेहराई की महिला समूह सदस्य ने बताया कि समूह की महिलाएँ सेंटिंग का कार्य करती हैं, तो उन्होंने कहा कि आवास योजना के कार्य इन्हीं समूहों को दिये जायेंगे। मऊ की वैशाली डोगले ने कहा कि वे पढ़कर भारतीय पुलिस सेवा में जाना चाहती हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रसन्न हुए जब जुड़मनियाँ मुरली की सुश्री सरिता ने बताया कि जल परीक्षण में कौन-कौन से मुख्य पहलू होते हैं।

मुख्यमंत्री ने बताईं ग्रामों की विशेषताएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल घोषित ग्रामों के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान संबंधित ग्रामों की विशेषताओं का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीहोर जिले के ग्राम धामंदा के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान शहीद जितेंद्र वर्मा का उल्लेख भी किया। शहीद के परिवार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाभार्थियों से बातचीत के क्रम में ग्राम सहराई के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान कहा कि यह हर्ष की बात है कि इस ग्राम के श्री दीपेश जैन इसरो के लिए कार्य कर रहे वैज्ञानिक हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अन्य ग्रामों की विशेषताओं का उल्लेख भी बातचीत के दौरान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नीमच के उम्मेदपुरा ग्राम के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान वहां की विश्व प्रसिद्ध बंधेज साड़ी और नांदना का उल्लेख किया। नांदना अर्थात वस्त्र छपाई की पारम्परिक कला पूरे भारत में अनूठी है। इसी उम्मेदपुरा की ठप्पा छपाई(ब्लाक प्रिंटिंग)भी मशहूर है। मुख्यमंत्री द्वारा इन विशेषताओं की जानकारी बताए जाने पर ग्रामवासी भी आश्चर्य चकित हुए। इस कला और व्यवसाय के विकास के लिये उद्योग क्षेत्र निर्मित होने से व्यवसाय विकसित हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस दिशा में समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जल जीवन मिशन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी संचालन के लिये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को बधाई दी। मुख्यमंत्री को ग्रामीण महिलाओं ने नल से जल मिलने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम धन्यवाद-पत्र भी सौंपे। छिंदवाड़ा के महिला स्व-सहायता समूह द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान का मोर मुकुट पहनाकर सम्मान किया गया और समूह द्वारा निर्मित कागज के संतरे भेंट किये गये। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने भी संबोधित किया। अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मलय श्रीवास्तव ने आभार माना।

कलेक्टर ने किया शासकीय उचित मूल्य दुकान मऊ एवं साखी का निरीक्षण

शहडोल : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती वंदना वैद्य ने जनपद पंचायत ब्यौहारी के भ्रमण के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकान मऊ का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने शासकीय उचित मूल्य दुकान मऊ के राशन विवरण बोर्ड की जानकारी का निरीक्षण किया तथा बोर्ड में राशन की विधिवत जानकारी पाए जाने पर कलेक्टर ने राशन दुकान संचालक की प्रशंसा की। कलेक्टर ने वहां की स्थानीय निवासी राम सिंह, बुधवा बाई तथा ज्ञानवती सिंह से चर्चा की तथा राशन दुकान में सही समय में राशन मिलता है अथवा नहीं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड के संबंध में ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त की, ग्रामीणों ने बताया कि अभी उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, जिस पर कलेक्टर ने तहसीलदार ब्यौहारी को घर-घर भ्रमण कर आयुष्मान कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने चावल, गेंहू एवं केरोसिन स्टॉक का भी निरीक्षण किया तथा स्टॉक के संबंध में उचित मूल्य दुकान संचालक से चर्चा करते हुए जानकारी प्राप्त की।

कलेक्टर ने उचित मूल्य दुकान में राशन लेने आए हितग्राही श्री कोमल प्रसाद से चर्चा की। उन्होंने बताया कि उन्हें समय-समय पर राशन प्राप्त हो जाता है। इस दौरान कलेक्टर ने दुकान में विधिवत साफ-सफाई एवं कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सैनिटाइजर एवं मास्क तथा जो भी हितग्राही आते हैं उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक-एक करके राशन मुहैया कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार ब्यौहारी श्री अभयानंद शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

स्वीकृत राशन से कम राशन मिलने पर सीएम हेल्पलाइन 181 पर करें शिकायत

मुरैना : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले के ऐसे उपभोक्ता, जिन्हें एकमुश्त राशन मिल रहा है। उन उपभोक्ताओं को पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाने पर दिये गये राशन की समस्त जानकारी दी जाती है। उचित मूल्य दुकान संचालक-विक्रेता द्वारा यदि किसी उपभोक्ता को स्वीकृत राशन से कम राशन वितरित किया जाता है, तो उपभोक्ता सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता स्वीकृत राशन की जानकारी कई तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता प्राप्त राशन की जानकारी पीओएस मशीन से जनरेट होने वाली पावती पर्ची से पावती प्रत्येक पीडीएस शॉप कीपर को उपभोक्ता को अनिवार्य रूप से देनी चाहिये प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होने वाले एसएमएस के माध्यम से भी राशन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एसएमएस के माध्यम से राशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर पीओएस मशीन पर अवश्य रजिस्टर्ड कराएं।

(पृष्ठ 1 का शेष)

सहकारी संस्थाओं द्वारा किए गए....

नौगाँव, जिला धार को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक समिति (प्र-संस्करण) के क्षेत्र में प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित, रेहटी, जिला सीहोर को और सर्वश्रेष्ठ महिला सहकारी समिति (महिला) में इंदौर जिले की स्वश्रयी महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित को प्रथम पुरस्कार दिया गया।

सहकारिता आयुक्त श्री संजय गुप्ता, अपर आयुक्त सहकारिता श्री अरुण माथुर, क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम श्री आर.के. मंगला, एम.डी. अपेक्स बैंक श्री पी.एस. तिवारी, एम.डी. आवास संघ श्री अरविंद सिंह सेंगर और एम.डी. बीज संघ श्री अमरीश सिंह भी उपस्थित थे।

(पृष्ठ 1 का शेष)

माँ, बहन, बेटियों के सशक्तीकरण के लिए.....

साथ ही बेटियों का घर ठीक से बस जाए इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में अब तक 40 लाख से अधिक बेटियाँ लाड़ली लक्ष्मी बनी हैं। राज्य सरकार लाड़ली लक्ष्मी-दो योजना शीघ्र ही क्रियान्वित करने वाली है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण सबसे पहले मध्यप्रदेश में दिया गया। महिलाओं के लिए संविदा शाला शिक्षक के 50 प्रतिशत पद पर तथा पुलिस की नौकरी में 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं ने भी आत्म-विश्वास के साथ काम कर नया इतिहास रचा है, यह बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। इंदौर पाँच बार स्वच्छता में प्रथम आया है, वहाँ की मेयर एक महिला है। महिला सरपंच भी अनुकरणीय कार्य कर रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आर्थिक सशक्तीकरण आत्म-सम्मान और आत्म- विश्वास के लिए जरूरी है। महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त हों, बहनों की आमदनी बढ़े, यह महिलाओं के संपूर्ण सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है। आजीविका मिशन में जुड़ी प्रत्येक महिला की न्यूनतम दस हजार रूपए प्रतिमाह आय हो, इस दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्यरत है। बैंकों से सहज और सरल रूप से महिलाओं को ऋण प्राप्त हो, इस उद्देश्य से प्रतिमाह बैंकों के साथ सघन बैठकें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाएँ रूपए-पैसे के डिजिटल लेन-देन के तरीकों को अपनाएँ। आजीविका मिशन की अवधारणा के 13 सूत्र को आत्म-सात करते हुए महिलाएँ पूरे आत्म-विश्वास से आगे बढ़ें, राज्य सरकार हर कदम पर महिलाओं के साथ है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में भी महिलाओं की सक्रियता से बदलाव आ रहे हैं। महिला स्व-सहायता समूहों को नशामुक्ति, बाल विवाह की रोकथाम, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों में सामाजिक व्यवहार में सकारात्मक बदलाव के लिए भी निरंतर प्रयास करने चाहिए।

मारूति वैन में चलती है रूबीना की कपड़े की दुकान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न जिलों के स्व-सहायता समूह के सदस्यों से वर्चुअली संवाद भी किया। देवास जिले की जागरूकता आजीविका स्व-सहायता समूह की श्रीमती रूबीना बी ने बताया कि वे मजदूरी करती थी। इसके बाद समूह से जुड़कर उन्होंने गाँव में ही कपड़े की दुकान लगाना आरंभ किया। इससे हुई आय में वृद्धि से रूबीना ने मारूति वैन खरीदी। अब वे आसपास के गाँवों में भी कपड़े बेचने जाती हैं। समूह से जुड़ने के बाद अब उनकी प्रतिमाह आय 25 से 30 हजार रूपए के बीच है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रूबीना के संघर्ष और सफलता की कहानी सुन, उन्हें प्रोत्साहित करते हुए संपूर्ण प्रदेश के स्व-सहायता समूहों से कहा कि - "ताली बजाओ रूबीना के लिए"।

समाज की आवश्यकता के अनुरूप व्यवसायों में प्रशिक्षण लें महिलाएँ

धार के जागृति आजीविका समूह की श्रीमती ममता सोनगरा ने बताया कि वे गाँव में साड़ी की दुकान के साथ ब्यूटी पार्लर का संचालन करती हैं। इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शहरों के साथ गाँवों में आए सामाजिक और व्यक्तिगत बदलाव के परिणामस्वरूप गाँवों में भी ब्यूटी पार्लर की माँग बढ़ी है। अत: महिलाएँ, समाज की आवश्यकता के अनुरूप व्यवसायों में प्रशिक्षण लें। इससे ऐसे व्यवसायों में प्रशिक्षण लेकर गाँव में ही ब्यूटी पार्लर या अन्य ऐसे कार्य आरंभ किए जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ने बढ़ाया व्यवसाय

शहडोल जिले की कपिल आजीविका स्व-सहायता समूह की श्रीमती आशा राठौर ने स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद सेन्ट्रिंग कार्य के लिए प्लेटे किराए पर देने का कार्य आरंभ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में बन रहे आवासों के परिणामस्वरूप इनका व्यवसाय अच्छा चल रहा है और प्रतिमाह 25 से 30 हजार की आय हो रही है।

रेस्टोरेंट में मामा भी आएगा और मामी को भी संग लाएगा

श्योपुर जिले के महात्मा गांधी आजीविका स्व-सहायता समूह की श्रीमती सरोज बैरवा ए.एम. प्रसादम नाम से दीदी कैफे संचालित कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जब ए.एम. का मतलब पूछा तो सरोज ने बहुत सहजता से बताया कि ए.एम. मतलब आजीविका मिशन है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्रीमती सरोज बैरवा से दीदी कैफे के संचालन, उनके द्वारा बनाए जा रहे व्यंजनों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। श्रीमती सरोज ने मुख्यमंत्री श्री चौहान से मनुहार करते हुए कहा कि - "मामाजी आप रेस्टोरेंट जरूर पधारें।" इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि - "रेस्टोरेंट में मामा भी आएगा और मामी को भी संग लाएगा।"

मास्टर ट्रेनर सुधा से सीएम बोले - "वेरी नाइस सुधा जी-आगे बढ़ते रहिए"

बड़वानी जिले के सरस्वती आजीविका स्व-सहायता समूह की श्रीमती सुधा बघेल ने स्व-सहायता समूह से जुड़कर खेती, बकरी पालन का कार्य आरंभ किया। वे अब राष्ट्रीय सामुदायिक मास्टर ट्रेनर के रूप में हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्य में प्रशिक्षण देने जाती हैं। मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्हें एक दिन का 2 हजार रूपए मानदेय प्राप्त होता है। श्रीमती सुधा बघेल की मासिक आय 22 ये 25 हजार रूपए है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि - "वेरी नाइस सुधा जी-आगे बढ़ते रहिए।"

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की ऋण राशि वितरित

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्व-सहायता समूह के अध्यक्ष/सचिवों को प्रतीक स्वरूप ऋण राशि का वितरण किया। उन्होंने सीहोर जिले के गंगा स्व-सहायता समूह को पशुपालन गतिविधियों के लिए 4 लाख, भोपाल के श्री राम स्व-सहायता समूह को डेयरी गतिविधियों के लिए 6 लाख, विदिशा जिले के रामकृष्ण स्व-सहायता समूह को पशुपालन के लिए 6 लाख, रायसेन के शिवाय स्व-सहायता समूह को सिलाई गतिविधियों के लिए 5 लाख 75 हजार और राजगढ़ जिले के भोलेनाथ स्व-सहायता समूह को डेयरी व्यवसाय के लिए 6 लाख 66 हजार रूपए के चैक प्रदान किए।

स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने स्थानीय उत्पादों को बढावा देना होगा- श्रीमती अमिता चपरा

वोकल फॉर लोकल से महिलाएं होगी आत्मनिर्भर- श्रीमती चपरा

शहडोल : देश के प्रधानमंत्री की मंशा वोकल फॉर लोकल को हम सब तभी साकार कर सकेंगे जब स्थानीय उत्पादों से विभिन्न प्रकार की सामग्रियां तैयार कर उनके बेहतर मार्केटिग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सकें इस हेतु स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिला सदस्यों को इनका प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के नये आयामों से जोड़ना होगा। जिससे वे अपने बेहतर जीविकोपार्जन हेतु छोटे-छोटे उत्पाद तैयार कर एवं उन्हें बेचकर अपनी आमदनी बढाने में सक्षम होगी। हमारे प्रदेश एवं जिले के अनेक उत्पाद जिनसे बेहतर सामग्रियां तैयार कर उन्हें बिक्री कर यह काम संभव हो सकेगा। प्रधानमंत्री ने देश में 100 करोड़ रूपये का महिला कोष बनाकर उससे महिलाओं के जीवन को सुदृढ़ बनाने की मंशा जागृत की है। उन्होंने कहा कि इसी दिशा में मैं प्रदेश के शहडोल जिलों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महिलाओं को स्व सहायता समूहों के माध्यम से विकसित करने का काम करने के लिए प्राथमिकता के साथ काम करूंगी। उन्होंने नींबू के छिलके को फेंकने के वजह उसके बेहतर पेस्ट बनाने का टिप्स बताते हुए कहा कि नींबू के छिलके को पीस कर उसमें सेंधा नमक, अजवाइन, हींग, लहसुन एवं काला नमक मिलाकर स्वास्थ्यवर्धक एवं स्वादिष्ट पेस्ट या चटनी बनाई जा सकती है। स्व-सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के कार्य हम सब को मिलकर करने होंगे जिससे महिलाओं को रोजगार के साथ-साथ आमदनी

के स्त्रोत भी सृजित होंगे। यह विचार अध्यक्ष महिला वित्त एवं विकास निगम श्रीमती अमिता चपरा ने आज स्थानीय कल्याणपुर में संचालित सह जीवन समिति के उत्पादों के अवलोकन अवसर पर व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि सह जीवन समिति एक अच्छी परिकल्पना के साथ नाम के सहित काम को धरातल पर उतार रही है यह स्वय सेवी संस्था अन्य संस्थाओं से हटकर है यहां दिये जा रहें अनेक उत्पादों के विषयवार प्रशिक्षण प्राप्त कर लोग अपनी आय को बढाएगें तथा इनसे प्रशिक्षण लेकर महिलाएं स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनेगी। इस मौके पर उन्होंने गेंहू, सोयाबीन, मूंगफली, मूंगदाल, घी एवं मिश्री से निर्मित प्रोटीन पाउडर, कच्चा पपीता की बड़ी, मुन्गा पत्ती की बड़ी, अमरू के फूल, महुआ के उत्पाद, मोंवा घास, लेवन ग्रॉस, सतावरी, सोंठ का त्रिकटयुक्त गुढ, तिलवारिया का बिस्कुट आदि स्थानीयता की वस्तुओं को बढावा देने की अन्य सामग्रियों का भी अवलोकन किया एवं उत्पादों को स्वय क्रय भी किया। इस मौके पर मनीषा माथनकर एवं गिरिधर माथनकर, संचालक सहजीवन समिति ने कहा कि जन सहभागिता से टीकाऊ विकास के प्रति संकल्पित महिलाओं के समग्र विकास हेतु सक्रिय यह संस्था 21 वर्षों से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सामाजिक,सांस्कृतिक व अध्यात्मिक व्यवस्थाओं को आगे बढाने के उददेश्य से जिले में 10 हजार परिवारों को स्व-सहायता समूह से जोड़ा गया है ग्राम स्वरोजगार व्यवस्था के तहत एनजीओ का कार्य अनेक क्षेत्रों में लोंगो प्रशिक्षित कर उनके जीवन में बदलाव लाना है। उन्होंने वाटर शेड योजना का उपयोग सब्जी, फलदार व औषधीय पौधों का विकास करने, उद्यानिकी विभाग के साथ मिलकर कार्य करने मुर्तरूप दिया जा रहा है साथ ही जिले की 5697 वर्ग किलो मीटर की भूमि को विविध रूप से विकसित करने नागरिकों के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पौराणिक चींजो का संरक्षण, संवर्धन एवं प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन तथा जल संरक्षण के कार्य भी किये जा रहे हैं। साथ ही देश में मानव व प्रकृति को संरक्षित करने युवाओं के सुझाव लेकर भी कार्य किये जाएगें। उन्होने कहा कि जिले में नर्मदा, सोन, जोहिला जैसी बड़ी नदियों और अनेकों जड़ी-बुटियों की प्रचूर मात्रा में बहूल्यता है। अध्यक्ष महिला वित्त विकास निगम ने सहजीवन समिति के प्रांगण में स्थापित माला बनाने, तुलसी के पौंधों, एक पेड़ में कई बिरायिटी के आम के पौंधे सहित अन्य औषधीय पौंधों की पौधशालाओं का भी अवलोकन किया और उनकी प्रक्रियाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी हासिल की। अध्यक्ष ने आंवला लड्डू, आंवला जल जीरा, आंवला सौंप, कच्ची हल्दी व अदरक का अचार, हैंड बैग, लाल मिर्ची की चटनी आदि अनेकों उत्पादों का अवलोकन किया एवं उनकी निर्माण प्रक्रियाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी हासिल प्राप्त की।

इस मौके पर परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास श्रीमती जशवंत कौर हूरा श्री रवीन्द्र वर्मा, श्री सुनील मिश्रा, श्री होल्कर सिंह परस्ते, श्री अभिषेक श्रीवास्तव, श्री मुकेश जेठानी, श्री इस्ताक खान, श्री राकेश सोनी सहित अन्य लोग उपस्थित थें।

किसान पंजीयन के लिए रतलाम जिले में 65 पंजीयन केंद्र स्थापित

रतलाम : आगामी रबी मौसम में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के मद्देनजर रतलाम जिले में 65 पंजीयन केंद्रों का गठन किया गया है, जहां किसानों का पंजीयन किया जाएगा। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में पंजीयन केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है।

जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.एच. चौधरी ने बताया कि प्रत्येक पंजीयन केंद्र पर एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। श्री चौधरी ने बताया कि किसानों का पंजीयन 5 फरवरी से आरंभ होगा जो 5 मार्च तक चलेगा। पंजीयन प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक होगा। नोडल अधिकारी निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। पंजीयन केंद्रों पर किसानों की सुविधा को दृष्टिगत मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, छाया, बैठक व्यवस्था, शौचालय आदि सुनिश्चित की गई हैं। कोविड-19 गाइड लाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, हाथ धुलाई, साबुन की व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक पंजीयन केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पंजीयन फार्म उपलब्ध रहेंगे।

किसान अपने मोबाइल से कर सकेंगे गेहूं उर्पाजन के लिए पंजीयन

रतलाम : रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जित करने के लिए किसानों की सुविधा हेतु किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। अब किसान स्वयं के मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। किसान द्वारा निम्नलिखित स्थानों/तरीकों से पंजीयन कराया जा सकेगा।

जिले में हर साल होता है 30 करोड़ का शहद उत्पादन

मुरैना : आदिवासी अंचल पहाड़गढ़ के धूरकूड़ा गांव में तैयार होने वाला शहद अब पूरे देश में अपनी मिठास घोलेगा। दरअसल मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने धूरकूड़ा गांव के स्व-सहायता समूह द्वारा तैयार किये जा रहे शहद की ब्रांडिग ''विंध्यावैली'' के नाम से करने का अनुबंध किया है। इससे समूह को उसके उत्पाद का बेहतर दाम मिलेगा और मुरैना में पैदा होने वाले शहद को एक नई पहचान भी मिलेगी। गौरतलब है कि एक जिला-एक उत्पाद के तहत एक नवंबर को मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने धूरकूड़ा गांव के सांई कृपा स्व-सहायता समूह के साथ अनुबंध किया है। इसके तहत समूह द्वारा तैयार किये जाने वाले शहद को विंध्यावैली के नाम से पैक्ड कर देशभर की मार्केट में पहुंचाया जायेगा। मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड इस शहद की देशभर में ब्रांडिग करेंगी। जिला खादी बोर्ड मुरैना के श्री केएन गुप्ता, जिला पंचायत के सीईओ श्री रोशन कुमार सिंह, श्री दिनेश तोमर, श्री जगदीश किरार की मौजूदगी में समूह को इसका अनुबंध पत्र भी सौंपा गया। इस मौके पर समूह की दीदी आराधना सिंह धाकड़, अनीता धाकड़, रामस्वरूप धाकड़, सरबदी धाकड़, रविता शक्या, मीणा, समीना, रेणु, सुरक्षा, सरस्वती, लीलावती आदि भी मौजूद थीं।जिले में हरसाल होता है 30 करोड़ का शहद उत्पादन जिले में हरसाल 300 करोड़ रूपये की कीमत का शहद उत्पादन होता है, लेकिन अभी तक किसानों द्वारा पैदा किये जाने वाले शहद पौने-पौने दामों में बेच दिया जाता है। यहां बतां दे कि जिले में 80 हजार बॉक्स मधुमक्खी पालन के लिये है। इस कारोबार में 5 हजार से अधिक किसान जुड़े हुये है, जिनमें महिलाओं की संख्या 1 हजार से अधिक है। शहद की ब्राडिंग के लिये एपीएफओ से जुड़े किसान हर साल तीन टन शहद का उत्पादन करने वाले पांच हजार से अधिक शहद उत्पादक किसान एफपीओ (फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर) से भी जुड़ने की तैयारी में है। केन्द्र सरकार के कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने देश के पांच प्रांतों के लिये एफपीओ का शुभारंभ किया। इसमें म.प्र. से अकेले मुरैना जिला चयनित हुआ है। इस एपीएफओ से जिले में 5 से 6 टन शहद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया। किसानों द्वारा तैयार किये जाने वाले शहद को स्वयं के द्वारा ही प्रोसेस करके नाफेड की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जायेगा, जिससे इनकी आय बढ़ेगी।

हायर डिप्लोमा एंड को-ऑपरेटिव मेनेजमेंट (HDCM) पाठ्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों का अध्ययन-भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न

भोपाल : मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के द्वारा दिनांक 01.11.2021 से 31.03.2022 तक संचालित आनलाईन सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (हायर डिप्लोमा एंड को-ऑपरेटिव मेनेजमेंट (HDCM) आयोजित किया गया है, जिसमें व्यवसाय विकास नियोजन विषयान्तर्गत अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को क्षेत्र की एक पेक्स संस्था एवं पांच अन्य सहकारी संस्थाओं में अध्ययन भ्रमण कर सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली, वित्तीय प्रबंध, व्यवसायिक प्रबंध एवं भविष्य की कार्ययोजनाओं तथा अन्य जानकारी प्राप्त कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाना होती है। इसी कड़ी में छतरपुर जिले से संबंद्ध प्रशिक्षणार्थियों द्वारा श्री एस.के. गौतम, प्र.प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, नौगांव के नेतृत्व में बुंदेलखण्ड महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, देरी रोड, छतरपुर, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सदभाव नागरिक सहकारी बैंक, वृहत्ताकार सहकारी समिति मर्यादित, पीरा (बमीठा), जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा बमीठा का अध्ययन-भ्रमण किया गया।

श्री व्ही .के. बर्वे, प्र.प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर द्वारा जिले की प्रियदर्शनी सुविधा स्व-सेवा केन्द्र, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित शाखा जबलपुर, एम.पी. प्रिटिंग प्रेस औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, जबलपुर, डी.वृहन महाराष्ट्र साख समिति, जबलपुर, दी इंडियन कॉफी हाउस वर्क्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि., जबलपुर का अध्ययन-भ्रमण कराया गया। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल के प्र.प्राचार्य श्री गणेश प्रसाद मांझी द्वारा भोपाल जिले से संबंद्ध प्रशिक्षणार्थियों को सुविधा सहकारी साख संस्था, भोपाल, एग्रीकल्चर बिजनेस एंड डेवल्पमेंट, को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि. भोपाल, आस्था महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल, म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, भोपाल, म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल एवं कृषक सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बैरागढ़-चीचली का अध्ययन-भ्रमण कराया गया।

धान की मिलिंग क्षमता बढ़ाने के लिए मंडी टैक्स में दी जाएगी छूट

तैयार उद्योग विभाग ने कैबिनेट के लिए बनाया प्रस्तादव

भोपाल। मध्यप्रदेश में धान का क्षेत्र और उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार रिकार्ड 45 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। इससे किसानों को तो लाभ हो गया पर सरकार की चिंता बढ़ गई है। क्योंकि समय पर मिलिंग (धान से चावल निकालना) नहीं होने पर धान डंप पड़ा है। केन्द्र सरकार सेन्ट्रल पूल में धान नहीं लेती है। पिछले सालों का पौने चार लाख टन से ज्यादा धान केंद्र सरकार लेने से इन्कार कर चुकी है। इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश में राइस मिल की स्थापना को लेकर प्रयास किए जा रहे है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर उद्योग विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें नई मिल की स्थापना करने या मौजूदा मिल की क्षमता में वृद्धि करने या मंडी टैक्स से छूट देने के साथ निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही मिलर को यह छूट भी रहेगी कि वो उत्तरप्रदेश, ओडिसा, छत्तीसगढ़, बिहार सहित अन्य राज्य से धान लाकर मिलिंग करता है तो वह धान भी मंडी शुल्क से मुक्त रखा जाएगा।

प्रदेश में छोटी-बड़ी 739 राइस मिल है। इनमें से लगभग तीन सौ के पास शार्टेक्स प्लांट भी है। इससे चावल की ग्रेडिंग की जाती है। लगभग 160 मिलर ने संयंत्र अपग्रेड करने की बात कही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि धान का रकबा और उत्पादन जिस तरह से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए मिलिंग की क्षमता बढ़ानी होगी। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। वहीं मिलिंग न हो पाने की वजह से धान खरीदने वाली एजेंसियों (नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य सहकारी विपणन संघ) को घाटा उठाना पड़ रहा है क्योंकि केन्द्र सरकार सेंट्रल पूल में धान लेने से इन्कार कर देती है। 2017-18 की एक हजार 250 और 2019-20 की तीन लाख 82 हजार टन धान पड़ा है। इसे अब सरकार नीलाम करने जा रही है। इसमें चार सौ करोड़ रूपये से अधिक का नुकसान संभावित है। यह स्थिति आगे न बने, इसके लिए नई राइस मिल के साथ मौजूदा मिलों की क्षमता वृद्धि के प्रयास किए जा रहे है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की पंजीयन तिथि बढ़ी अब 31 मार्च तक हो सकेगा आवेदन

भोपाल : आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में पंजीयन के लिए अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई गई हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना के प्रमुख बिंदुओं में ई.पी.एफ.ओ. के साथ पंजीकृत पात्र स्थापनाओं के नए कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन। नए कर्मचारी, जो 15 हजार रुपए से कम मासिक वेतन प्राप्त करते है। पंजीकरण की तिथि से 24 वेतन माह के लिए लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। प्रोत्साहन का भुगतान 1,000 कर्मचारियों तक नियोजित करने वाली स्थापनाओं में कार्यरत नए कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारियों तथा नियोक्ता, दोनों का अंशदान, अर्थात वेतन का 24 प्रतिशत, 1,000 से अधिक कर्मचारियों वाली स्थापनाओं में कार्यरत नए कर्मचारियों के संबंध में केवल कर्मचारियों का अंशदान अर्थात वेतन का 12 प्रतिशत, एक अक्टूबर, 2020 के बाद ई.पी.एफ.ओ. के साथ पंजीकृत स्थापनाएं सभी नए कर्मचारियों के संबंध में लाभ प्राप्त कर सकेगी।

शीघ्र आयें प्रवेश पायें
म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित , भोपाल द्वारा संचालित
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध
PGDCA (योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण) कुल फीस 9100/-
DCA (योग्यता -10 +2 उत्तीर्ण) कुल फीस 8100/-
संपर्क :-
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केंद्र
ई- 8/77 शाहपुरा ,त्रिलंगा ,भोपाल फोन : 0755-2926160 , 2926159
मो. 8770988938 , 9826876158 Website-www.mpscu.in
Web Portal-www.mpscuonline.in Email-rajyasanghbpl@yahoo.co.in
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
किला मैदान इंदौर, म.प्र. पिन – 452006
फोन- 0731-2410908 मो. 9926451862, 9755343053
Email - ctcindore@rediffmail.com

सहकारी शिक्षक श्री शुक्ला का निधन

इंदौर : सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक एवं कई सहकारी संस्थाओं के मार्गदर्शक पंडित श्री शिवमोहन शुक्ला का 86 वर्ष की आयु में इंदौर में निधन हो गया। श्री शुक्ला सहकारी कार्य संस्थान शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के 30 वर्षों तक संचालक, सचिव एवं उपाध्यक्ष पद पर रहें। आप अन्न पूर्णा साख सहकारी संस्था इंदौर के अध्यक्ष एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल के कई वर्षों तक संचालक भी रहे । शिक्षा विभाग में एक आदर्श शिक्षक के रूप में आपकी पहचान थी। सहकारिता के क्षेत्र में भी आपकी अच्छी पकड़ थी। इसलिए आपको सहकारी शिक्षक कहते थे।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।